

सेवा में,  
भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त  
अशोक रोड, नई दिल्ली

9 जनवरी 2014

विषय: जन प्रतिनिधित्व क़ानून की धारा 29(ए) के अन्तर्गत समाजवादी पार्टी का  
रेजिस्ट्रेशन रद्द करने के लिए अनुरोध

श्रीमान !

उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी तथा उसकी सरकार जन प्रतिनिधित्व क़ानून की धारा 29-ए(5) के विपरीत राज्य के मुज़फ़्फ़रनगर व शामली ज़िलों में सितम्बर 2013 से अब तक निम्न अवमाननाओं की दोषी हुई है। उन्होंने (अ) क़ानून के अनुसार अपना कर्तव्य पूरा न करके संविधान के प्रति अपनी प्रतिज्ञा और वचन को नहीं निभाया; (ब) समाजवाद, धर्मनिर्पेक्षता तथा लोकतंत्र के संवैधानिक सिद्धांतों का उल्लंघन किया; तथा (त) राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने में विफल रहे। इसी के साथ समाजवादी पार्टी एवं उसकी सरकार नागरिकों की एक बड़ी संख्या के जान व माल की सुरक्षा में भी अक्षम रहीं। इस पार्टी एवं उसकी सरकार ने बे-घर हुए हज़ारों लोगों के पुनर्वास व कल्याण के लिए अपेक्षित उपाय नहीं किए। 50 हज़ार से अधिक लोगों के मानवीय अधिकारों एवं हितों की, केवल आने वाले लोकसभा चुनावों में पार्टी का हित साधे रखने के लिए, अनदेखी की और उन्हें स्वार्थ-सिद्धि के लिए भेंट चढ़ा दिया। जिसके परिणाम स्वरूप यह असहाय और पीड़ित लोग ग़रीबी, अशिक्षा, बीमारियों तथा असमानता के गढ़ों में गिर गए। उन से शिक्षा का हर अवसर छिन गया। अपने निवास स्थानों से विस्थापित हो जाने की वजह से उनकी धार्मिक स्वतंत्रता बुरी तरह प्रभावित हुई। वे लोग ईदुलअज़हा, मुहर्रम और मीलादुन्नबी जैसे अपने धार्मिक, सांस्कृतिक एवं परिवारिक त्यौहारों को मनाने से वंचित रह गए। ये त्यौहार शरणार्थी शिविरों में उनके रहते हुए ही गुज़र गए। संविधान में दिए गए न्याय प्राप्ति के वचन से उन्हें वंचित रखा गया। ये लोग धार्मिक कटुता व दुराग्रह का निशाना बनाए गए। उनके धार्मिक स्थल तोड़े गए तथा उनका अपमान किया गया। ये लोग विस्थापित हो जाने के कारण वोट के अधिकार को इस्तेमाल करने की स्थिति में नहीं

रहे। इस तरह अपने मौलिक अधिकारों से ये वंचित हो गए। ये लोग अब सामाजिक गतिविधियों में पूरी तरह भाग नहीं ले सकते। इसके कारण राजनीतिक सामूहिकता में भागीदार बनने के इनके अधिकार को चोट पहुंची है जो कि लोकतंत्र की पहचान है। इस तरह अब स्वयं अपने जीवन को प्रभावित करने वाले सामूहिक निर्णयों में भागीदार बनने का अवसर उनके पास नहीं रहा।

2. अतः हमारा अनुरोध है कि धारा 129(ए)(5) के अनुरूप समाजवादी पार्टी का रजिस्ट्रेशन रद्द किया जाए।

3. इस सन्दर्भ में यह भी उचित होगा कि समाजवाद, धर्मनिर्पेक्षता एवं लोकतंत्र का लक्ष्यार्थ फिर से समझा जाए। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार समाजवाद का अर्थ है: “नागरिकों के कल्याण एवं विकास का प्रयास, यह लोकतंत्र का अंग है।” (कोलकाता की एन.जी.ओ गुड गवर्नेन्स इण्डिया फ़ाउण्डेशन की याचिका पर चीफ़ जस्टिस की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय खण्डपीठ का निर्णय, 2009)।

4. 15 अगस्त 1958 के एकाँनोमिक रिव्यू में पं० जवाहर लाल नेहरू ने अपने एक लेख में लिखा था: “हम समाज के कल्याण की बात करते हैं। क्या यह बात समाज का गठन करने वाले व्यक्तियों के कल्याण से कुछ अलग है ? जिस चीज़ को समाज का कल्याण माना जाता है उसके लिए यदि व्यक्ति की उपेक्षा की जाए या उसे भेंट चढ़ा दिया जाए तो क्या यह दृष्टिकोण उचित है ?

5. कई मुकदमों के निर्णयों में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात की पुष्टि की है कि: **समाजवाद** का उद्देश्य गरीबी, अशिक्षा, बीमारियों तथा असमानता का उन्मूलन है (सचिव एच.एस. सी. बनाम सुरेश), तथा उसका ध्येय शिक्षा की गतिविधियों के हर तरह के अवसर उपलब्ध कराना है (डी. एस .नाकर बनाम यूनियन ऑफ़ इण्डिया)।

6. प्रो. राजीव धवन ने संवैधानिक **धर्मनिर्पेक्षता** का अपना प्रसिद्ध विश्लेषण करते हुए भारतीय धर्मनिर्पेक्षता को तीन अवयवों में विभाजित किया है: (अ) धार्मिक स्वतंत्रता जिस में धार्मिक मान्यताएं तथा रीति रिवाज शामिल हैं, (ब) त्यौहारों में निष्पक्षता जो सरकार से सभी धर्मों के त्यौहारों में सहायता की अपेक्षा करती है, तथा (प) सुधारात्मक न्याय जिसमें उन मौलिक रीतियों को छोड़ कर जिन पर कोई नियम लागू नहीं किया जा सकता, शेष धार्मिक संस्थाओं तथा चलन का सुधार और उन्हें नियमित करना शामिल है।

7. माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बोमई निर्णय (ए. आई. आर. 1994 एस. सी. 1918) में यह कहा था कि धार्मिक उदारता एवं सभी वर्गों के साथ तथा उनके जान व माल एवं धार्मिक स्थलों की सुरक्षा के लिए

समान व्यवहार संविधान में उल्लिखित की गयी धर्मनिर्पेक्षता का अनिवार्य अंग हैं और धर्मनिर्पेक्षता देश की एकता के लिए अपरिहार्य है।

8. इसी तरह हम यह भी जानते हैं कि **लोकतंत्र** एक ऐसी शासन प्रक्रिया है जिस में सभी पात्र लोग मतदान द्वारा अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। यह एक ऐसी व्यवस्था है जिस में हर एक के साथ समान रूप से व्यवहार किया जाता है। लोकतंत्र का मूल गुण यह है कि सभी मतदाताओं को अपने सामाजिक जीवन में स्वतंत्रतापूर्वक एवं पूरी तरह से भाग लेने का अधिकार होता है। मतदाताओं के सामाजिक सरोकार एवं सामूहिक इच्छा की कल्पना पर जोर के मद्देनजर लोकतंत्र को राजनीतिक सामूहिकता के एक रूप में देखा जा सकता है क्योंकि इसे एक ऐसा शासन तंत्र कहा जाता है जिस में सभी पात्र नागरिकों को अपने जीवन को प्रभावित करने वाले निर्णयों में अपना मत बराबर से देने का अधिकार है।

9. सितम्बर 2013 से समाजवादी पार्टी तथा उत्तर प्रदेश में उसकी सरकार मुजफ्फरनगर तथा शामली जिलों में उपरोक्त सभी मोर्चों पर विफल रही है। 08 जनवरी 2014 को मुजफ्फरनगर और शामली के प्रभारी मंत्री विदेश यात्रा पर चले गए। और उसी दिन समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अपने गांव में चल रहे शीतकालीन उत्सव में नाच गानों का मनोरंजन लेने के लिए सिनेमा सितारों के साथ चले गए। जबकि सितम्बर 2013 से अब तक वह मुजफ्फरनगर व शामली के राहत शिविरों में दंगा पीड़ितों की स्थिति को अपनी आंखों से देखने के लिए एक बार भी नहीं गए। इस पूरे सदर्भ में आप निम्न रिपोर्टों को देख सकते हैं जो कि सितम्बर 2013 से प्रिन्ट व इलैक्ट्रॉनिक मीडिया में आ रही रिपोर्टों का एक नमूना भर हैं। कृपया जकात फ़ाउण्डेशन की वेबसाइट [zakatindia.org](http://zakatindia.org) पर उन वीडियो क्लिपिंग्स को भी देखें जिन में पीड़ित अपनी बिपता सुना रहे हैं:

1. UP: SP MLAs party, go on "study tour"; riot victims suffer, face FIRs

<http://ibnlive.in.com/news/up-sp-mlas-party-go-on-study-tour-riot-victims-suffer-face-firs/444064-37-64.html>

2. Muzaffarnagar riot-victims refuse to vacate Shamli camp (The Hindu, 5 January 2014)

<http://www.thehindu.com/news/national/other-states/muzaffarnagar-riotvictims-refuse-to-vacate-shamli-camp/article-5541323.ece>

3. Muzaffarnagar riots: Arrest warrant against camp organizer (Zee News, 5 January 2014)

<http://zeenews.india.com/news/uttarpradesh/muzaffarnagar-riot-arrest-warrant-against-malakupur-camp-organiser-901939.html>

4. Shamli authorities start evacuation from relief camps (Zee News 03 January 2014) <http://zeenews.india.com/news/uttar-pradesh/shamli-authorities-start-evacuation-from-relief-camps-901131.html>
5. Muzaffarnagar horror: Kids die of cold in relief camps (NDTV, 3 Dec 2013) <http://www.ndtv.com/video/player/news/muzaffarnagar-horror-kids-die-of-cold-in-relief-camps/300148>
6. One night at a relief camp in Shamli (NDTV, 14 Dec 2013) <http://www.ndtv.com/video/player/news/one-night-at-a-relief-camp-in-shamli/301689>
7. 11 children have died in relief camps, says Muzaffarnagar DM (Times of India (PTI), 14 Dec 2013) <http://timesofindia.indiatimes.com/india/11-children-have-died-in-relief-camp-muzaffarnagar-dm-says/articleshow/27368910.cms>
8. Three youngsters rape minor girl in Shamli (IBN Live, 22 Dec 2013) <http://ibnlive.com/news/three-youngsters-rape-minor-girl-in-shamli/441051-3-242.html>
9. Relief camps in riot hit UP districts in appalling condition: NHRC <http://ibnlive.in.com/news/relief-camps-in-riothit-up-districts-in-appalling-condition-nhrc/429749-3-2-242.html>
10. Muzaffarnagar riot victims refuse to vacate Shamli camp (Deccan Herald, 9 Jan 2014) <http://www.deccanheral.com/content/378664/muzaffarnagar-riot-victims-refused-vacate.html>
11. Muzaffarnagar riot victims refuse to vacate Shamli camp (post.jagran.com, 9 January 2014) <http://post.jagran.com/muzaffarnagar-riotvictims-refuse-to-vacate-shamli-camp-1388993433>
12. Muzaffarnagar riots: nearly 6000 names, 294 arrested; no arrest in rape cases yet (NDTV, 01 January 2014) <http://www.ndtv.com/article/india/muzaffarnagar-riots-nearly-6000-named-only-294-arrested-no-arrest-in-rape-cases-465751>

13. Muzaffarnagar: Months after riots gangraped women await justice (IBN Live, 2 January 2014)

<http://ibnlive.in.com/news/muzaffarnagar-months-after-riots-gangraped-women-await-justice/442827-3-242.html>

14. UP turns its back on Muzaffarnagar gangrape victims (Hindustan Times, 4 Dec. 2014)

<http://ibnlive.in.com/news/muzaffarnagar-months-after-riots-gangraped-women-await-justice/442827-3-242.html>

15. Riot victim at Muzaffarnagar relief camp raped by two youths (Times of India, 3 Nov 2013)

<http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2013-11-03/india/43627851-1-riot-victim-relief-camp-two-youths>

16. "They gang raped my daughters in front of my eyes; Muzaffarnagar riots victims too afraid to report to police (Daily Bhaskar, 16 Sept 2013)

<http://daily.bhaskar.com/article/UP-daughters-raped-in-front-of-mothers-muzaffarnagar-riots-victims-too-afraid-to-re-4376208.html>

17. A village in Muzaffarnagar Recounts Rapes and Murder By Pomposh Raina (New York Times, September 30, 2013)

[http://india.blogs.nytimes.com/2013/09/30/a-village-in-muzaffarnagar-recounts-rapes-and-murder/?\\_r=0](http://india.blogs.nytimes.com/2013/09/30/a-village-in-muzaffarnagar-recounts-rapes-and-murder/?_r=0)

18. The silence of Muzaffarnagar (Asian Age, Shiv Vishwanath, 31 Dec 2013)

<http://www.asianage.com/columnists/silence-muzaffarnagar-714>

अतएव, हमारा अनुरोध है कि समाजवादी पार्टी का रेजिस्ट्रेशन जन प्रतिनिधित्व क़ानून की धारा 29(ए) (5) के अनुसार तुरन्त रद्द किया जाए।

प्रार्थी,

(ह.)

मुम्ताज़ नजमी

सचिव,

जकात फ़ाउण्डेशन ऑफ़ इण्डिया

